

BARC Team : Nagendra Singh Khangarot
Vijay Goyal
Ashok Vaishnav
Radha Mohan Jogi

Adviser : Dr. Ginny Shrivastava

The Links : Policy to People and People to Policy



स्थानीय स्तर पर लिंग आधारित बजट (जेण्डर बजट) कैसे करेंगे पैरवी



संकलन कर्ता
सुब्रतो दत्ता

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
जयपुर

उ बजट अद्ययन राजस्थान केन्द्र

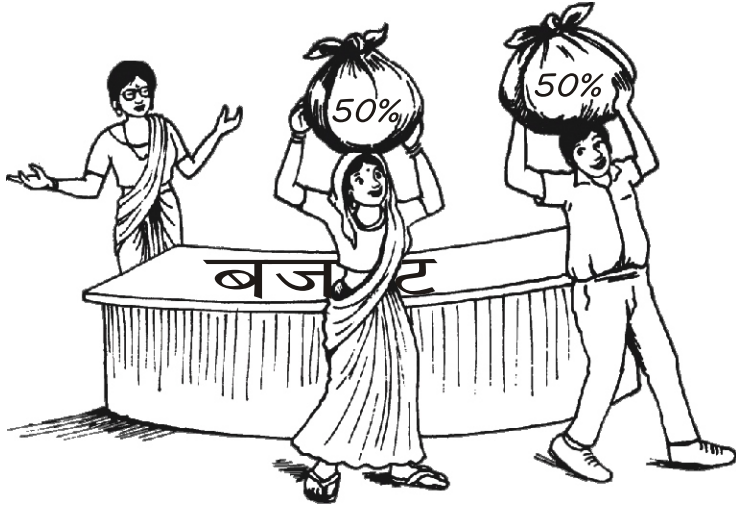
प्रकाशक : बजट अद्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रथम संस्करण : सितम्बर, 2006

मुद्रक : कल्पना ऑफसेट, जयपुर

बजट अद्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा सीमित प्रसार एवं
निःशुल्क वितरण के लिए प्रकाशित।

स्थानीय स्तर पर लिंग आधारित बजट
(जेण्डर बजट)
कैसे करेंगे पैरवी



संकलन कर्ता
सुब्रतो दत्ता

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं।	विषय	पृष्ठ
1.	सैक्स एवं जेण्डर के बीच में अन्तर क्या है ?	3
2.	क्या बजट बनाते समय जेण्डर को ध्यान में रखा जाता है?4	
3.	जेण्डर बजट तथा लिंग आधारित बजट	5
4.	लिंग आधारित दृष्टि से स्थानीय बजट का मूल्यांकन	6
5.	शिक्षा	7
6.	शिक्षा के क्षेत्रा में व्यय सम्बन्धित अध्ययन	9
7.	स्वास्थ्य	10
8.	प्रजनन सम्बन्धित समस्याएं	11
9.	जल	12
10.	अभ्यास	13

पहले हम समझें

सेक्स व जेण्डर के बीच में अन्तर क्या है ?

- ❖ किसी का सेक्स जैविक आधार पर निर्धारित किया जाता है – जैसे कि पुरुष है या महिला ।
 - पुरुष व महिला की सेक्स आधारित जो भूमिका है उसे सामान्यतः परिवर्तन करना कठिन है। उदाहरण स्वरूप, महिला द्वारा गर्भधारण करना एवं बच्चे को जन्म देना, इन सारी भूमिकाओं को परिवर्तन करना कठिन है।
- ❖ जेण्डर एक सामाजिक अवधारणा है। यह भूमिका परिवर्तनीय है। विभिन्न समाजों में जेण्डर को अलग-अलग दृष्टि से देखा जाता है।
जैसे :
 - कुछ समाजों में महिलाएं मुख्य रूप से सिर्फ घर का काम संभालती हैं, वहीं कुछ समाजों में महिलाएं बाहर निकलकर रोजगार भी करती हैं।

क्या बजट बनाते समय जेण्डर को ध्यान में रखा जाता है?

क्या सरकार की नीतियां एवं बजट को जेण्डर के आधार पर तैयार किया जाता है ? क्या नीति निर्धारित करते समय एवं बजट आवंटन करते समय पुरुषों एवं महिलाओं दोनों का ही ध्यान रखते हैं ?

- ❖ महिलाओं को हमारे देश में किस रूप में देखा जाये वह पुरुष पर निर्भर करता है। इसी तरह विभिन्न नीतियां निर्धारित करते समय महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दी जायेगी वह भी पुरुष पर ही निर्भर करता है।
- ❖ सरकार बजट बनाती है और बजट का पैसा खर्च भी करती है। सरकार में अधिकतर कौन से वर्ग के लोग हैं ? – मुख्यतः पुरुष वर्ग के लोग अधिक हैं।
- ❖ राजस्थान में पुरुषों की संख्या हैं 2 करोड़ 94 लाख 20 हजार और महिलाओं की संख्या 2 करोड़ 70 लाख 87 हजार। क्या सरकार बजट बनाते समय इन बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए विशेष ध्यान देती है ?

जेण्डर बजट तथा लिंग आधारित बजट

हां, अभी हम जेण्डर बजट की बात कर रहे हैं।

- ❖ क्या है यह लिंग आधारित बजट ?
- ❖ क्या हम पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग बजट बनाने की बात कर रहे हैं ?

नहीं। हम बात कर रहे हैं उन नीतियों की, योजनाओं की, कार्यक्रमों आदि के बजट की, जिसे बनाते समय राज्य की बालिकाओं और महिलाओं की समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि गरीबी का असर महिलाओं पर सबसे निर्मम रूप से पड़ता है। एक उदाहरण के रूप में, जैसे कि किसी गरीब परिवार में अचानक आय कम होने के कारण परिवार के खाने में कटौती हुई है। इस कटौती की शुरुआत पहले महिला से होती है।

ध्यान में रखना चाहिए की कोई भी बजट लिंग निरपेक्ष नहीं हैं। यदि कोई बजट लिंग केन्द्रित प्रतीत नहीं होता है तो जरूर वह बजट लिंग विवेकशून्य है। यह लिंग विवेकशून्यता तथा उदासीनता भी एक तरह से महिलाओं पर दृष्टि नहीं डालने का प्रयास है। महिलाओं से दृष्टि हटाकर हमारा गरीबी उन्मूलन का प्रयास कभी सफल नहीं होगा।

तो हमें जांच करनी चाहिए कि सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों में हो रहे व्यय को नीति निर्धारकों द्वारा लिंग आधारित दृष्टि से देखा जा रहा है या नहीं।

लिंग आधारित दृष्टि से स्थानीय बजट का मूल्यांकन

राज्य तो बहुत बड़ी बात है, हम इस पुस्तिका में जिला और ग्राम स्तर पर नीति, कार्यक्रम व विभिन्न व्यय को लिंग आधारित दृष्टि से कैसे मूल्यांकन किया जाए उसका तरीका समझेंगे।

1. स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए नीति व व्यय सम्बन्धित जो निर्णय लिए जाते हैं, उसमें :
 - ❖ कितनी महिलाओं को शामिल किया जाता है ?
 - ❖ इन निर्णयों में महिलाएं शामिल नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं ?
 - ❖ महिला एवं बालिका कल्याण सम्बन्धित जो निर्णय पुरुषों द्वारा लिये जाते हैं, क्या वे सभी निर्णय सही होते हैं ?
2. अगर निर्णय प्रक्रिया में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं तो क्या महिला प्रतिनिधियों की सोच व निर्णय को प्राथमिकता दी जाती है ?

शिक्षा

- ❖ आपके जिले/पंचायत में कुल कितने बालक एवं बालिकाएँ हैं ? इनमें से कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं (कितने छात्र एवं कितनी छात्राएँ) ?
- ❖ आपके जिले/पंचायत में निरक्षर बालक व बालिकाओं की संख्या कितनी है ? इनको शिक्षित करने के लिए बालक एवं बालिकाओं के बारे में अलग-अलग से क्या निर्णय लिये गया ?
- ❖ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों एवं छात्राओं का नामांकन अनुपात कितना है ?
- ❖ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों एवं छात्राओं का नामांकन अनुपात कितना है ?
- ❖ व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों एवं छात्राओं का नामांकन अनुपात कितना है ?
- ❖ उच्च शिक्षा में छात्रों एवं छात्राओं का नामांकन अनुपात कितना है ?
- ❖ छात्राओं का नामांकन छात्रों की तुलना में बहुत कम है तो उसके पीछे क्या कारण हैं ? छात्राओं का नामांकन बढ़ाने के लिए क्या निर्णय लिया गया है ?
- ❖ छात्रों एवं छात्राओं का ड्रापआउट अनुपात कितना है ? यदि छात्राओं का ड्रापआउट ज्यादा है तो उसके पीछे क्या कारण हैं ? छात्राओं का ड्रापआउट कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा के क्षेत्र में निम्न की समीक्षा की भी जरूरत है

- ❖ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा में नामांकित विद्यार्थियों में से संतुष्ट छात्रों एवं छात्राओं का अनुपात कितना है ? छात्राएँ ज्यादा असंतुष्ट हैं तो क्यों ? छात्र ज्यादा असंतुष्ट हैं तो क्यों ? छात्रों एवं छात्राओं का असंतोष दूर करने हेतु उनके लिए अलग-अलग क्या उपाय किये गये हैं ? माध्यमिक/उच्च माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र में ऐसी समीक्षा की जानी चाहिए।
- ❖ बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय सुविधा है या नहीं देखनी चाहिए। विशेष रूप से 12 वर्ष से अधिक की बालिकाओं में महावारी (menstruation) हेतु उनके लिए अलग व्यवस्था आवश्यक है।
- ❖ विद्यालय/कॉलेज/विश्वविद्यालय में महिला एवं पुरुष अध्यापक का अनुपात कितना है ? यह अनुपात छात्राओं एवं छात्रों के अनुपात के साथ समतुल्य है या नहीं ?

शिक्षा के क्षेत्रा में व्यय सम्बन्धित अध्ययन

गत वर्ष में आपके जिला/पंचायत में :

- ❖ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा में बालक एवं बालिका के लिए कितनी राशि व्यय की गई है ?
- ❖ बालक के लिए प्रति व्यक्ति व्यय राशि कितनी है और बालिका के लिए प्रति व्यक्ति कितनी राशि व्यय हुई ?

स्वास्थ्य

- ❖ आपके जिले में कुल कितने अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? उनमें से कितने अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र सिर्फ महिलाओं के लिए हैं ?
- ❖ जनाना अस्पताल/सामान्य अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र में पुरुष और महिला डॉक्टरों का अनुपात कितना है ?
- ❖ हर अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर एवं नर्स के अलावा बाकी कर्मचारियों के बीच में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात कितना है ?
- ❖ सामान्य अस्पताल में पुरुष एवं महिला मरीजों के पलंगों का अनुपात कितना है ?

प्रजनन सम्बन्धित समस्याएं और जेण्डर बजट

- ❖ क्या हर अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र में महिलाओं के लिए प्रजनन सम्बन्धित सुविधाएं हैं ?
- ❖ निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र आपके गांव से कितनी दूर है ?
- ❖ एक गर्भवती महिला को वहां पहुंचने के लिए कितना समय लगता है ?
- ❖ यह दूरी ज्यादा लगती है तो आपके गांव से कितनी दूरी पर स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए ?
- ❖ गर्भवती महिलाओं को समय पर टीका लगवाने की सुविधा मिलती है या नहीं ?
- ❖ क्या अस्पताल में गर्भवती महिला को लाने के लिए अम्बुलेंस सुविधा मिलती है ?
- ❖ क्या परिवार नियोजन हेतु पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र में अलग-अलग सुविधाएं हैं या नहीं ?



जल

गांवों के परिवारों में पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा चिंता कौन करता है ?

- ❖ महिलाएं करती हैं। क्यों ?
- ❖ क्योंकि पानी भरने की जिम्मेदारी महिलाओं के ही हिस्से में है ?

तो क्या जांच करनी चाहिए ?

- ❖ कुएं, नलकूप आपके गांव से कितनी दूरी पर हैं ?
- ❖ आप जिस पंचायत में रहते हो वहां कुएं खोदने व नलकूप लगाने से पहले क्या महिलाओं से चर्चा की जाती है ?



इसी प्रकार आप अन्य विभागों के बजट की लिंग आधारित दृष्टि से जाँच कर सकते हैं।

अभ्यास

पृष्ठ 14 पर राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग के बजट (2004-05 से 2006-07 तक) का सारांश एवं पृष्ठ 15-16 पर श्रम तथा रोजगार विभाग के बजट (2004-05 से 2006-07 तक) का सारांश संलग्न है (विस्तार के लिए राजस्थान सरकार की 2006-07 की बजट पुस्तिका देखें)। सहकारिता विभाग एवं श्रम तथा रोजगार विभाग के बजट का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

1. पहचान कीजिए जेण्डर सम्बन्धी कमियाँ क्या हैं।
2. जेण्डर विशेष व्यय मद की पहचान कीजिए।
3. किस मद से महिलाओं को ज्यादा मदद मिलती है ?
4. बताईये इस बजट को लिंग समानता की दृष्टि से कैसे बनाया जा सकता है ?

में

तालिका - 1 : सहकारिता, कोपरेशनद विभाग का बजट

लेखे		आय-व्ययक अनुमान		संशोधित अनुमान		आय-व्ययक अनुमान		सहस्र रूपयों में				
2004-2005		2005-2006		2005-2006		2006-2007		2006-2007				
आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें			
मिन्न		मिन्न		मिन्न		मिन्न		मिन्न				
13,14,96	"	16,04,14	1,25	14,53,53	1,25	"	निदेशन	रत्तमत	15,34,87	3,50	"	15,38,37
82	"	1	"	2	"	"	तथा प्रशासन प्रभूत*	1	"	"	"	1
74,80	5,48	71,49	7,00	75,11	5,50	"	शिक्षण	70,27	7,00	"	77,27	
8,37,13	"	10,97,40	"	10,68,99	"	"	सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा	11,34,52	"	"	11,34,52	
14,26	3,00	15,95	4,00	16,09	3,50	"	सूचना एवं प्रचार	16,73	3,80	"	20,53	
4,95	"	1	2	12,96	2	"	क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता	18,62	2	"	18,64	
4,52	31,50	5,60	3,21,56	6,08,88	4,33	1,88,09	अन्य सहकारी समितियों को सहायता	4,65	99,00	82,50	1,86,15	
4,78	"	1	"	1	"	"	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	1	"	"	1	
"	70	4,50	2,44	14,22	2,44	14,22	जनजातिय क्षेत्र उपयोग	"	62	1	63	
"	4,12	37,09	12,67	1,14,03	12,67	1,14,03	अन्य व्यय	"	1	1	2	
"	"	"	"	"	"	"	नवीन सेवा	"	"	"	"	"
22,55,40	44,80	1,96,38	27,94,60	3,48,94	7,37,13	26,37,02	रत्तमत	27,79,67	1,13,95	82,52	29,76,14	
82	"	"	1	2	"	"	प्रभूत	1	"	"	1	
22,56,22	44,80	1,96,38	27,94,61	3,48,94	7,37,13	26,37,04	वृहद योग	27,79,68	1,13,95	82,52	29,76,15	

नोट : * रत्तमत एवं प्रभूत की परिभाषा के लिए पृष्ठ 16 के अन्त में देखिये।
 स्रोत : बजट पुस्तिका 2006-07, राजस्थान सरकार

तालिका - 2 : श्रम तथा रोजगार :लेबर एण्ड एम्प्लायमेंट्स विभाग का बजट

सारांश

लेखे		आय-व्ययक अनुमान		संशोधित अनुमान		आय-व्ययक अनुमान		सहस्र रूपयों में	
2004-2005		2005-2006		2005-2006		2006-2007		2006-2007	
आयोजना भिन्न	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना भिन्न	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना भिन्न	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना भिन्न	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना भिन्न	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें
1,11,67	"	1,24,97	"	1,23,06	"	1,28,73	"	1,28,73	"
32	"	1	"	1	"	1	"	1	"
5,31,77	16,03	6,02,87	16,01	5,96,27	7,96	6,25,12	14,21	6,39,33	14,21
"	"	1	"	1	"	1	"	1	"
3,04,57	17,78	3,28,60	22,19	3,30,85	15,54	3,47,35	8,45	3,55,80	8,45
63,47	"	68,63	1	71,63	15,00	75,63	1	75,64	1
"	"	1,00	"	1,00	"	1,00	"	1,00	"
38,64	"	42,40	"	42,94	"	45,18	"	45,18	"
10,50,12	33,81	11,67,47	39,21	11,64,75	39,50	12,22,01	23,67	11,00	12,56,68
32	"	2	"	2	"	2	"	2	"
01 श्रम									
निदेशन तथा प्रशासन 1,28,73									
औद्योगिक सम्बन्ध- दत्तमत प्रभूत 1									
कार्य की परिशिष्टितया तथा सुखा 3,47,35									
सामान्य श्रम कल्याण 75,63									
बहुआ मजदूर का पुनर्वासि 1,00									
जनजातिय क्षेत्रा उपयोजना 45,18									
उप मुख्य शीर्ष-01-योग दत्तमत 12,22,01									
प्रभूत 2									
02 रोजगार सेवाएं									
निदेशन तथा प्रशासन 1,29,36									
अनुसन्धन सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 13,23									
रोजगार सेवाएं 3,55,84									
जनजातिय क्षेत्रा उपयोजना 15,83									
4: &: 6,00									
03 प्रशिक्षण									
शिक्षणकारों तथा स्वयंसेवकों 16,41,83									
औद्योगिक प्रशिक्षण दत्तमत 9,69,40									
संस्थान प्रभूत 1									
प्रशिक्ष, प्रशिक्षण 1,02,15									
जनजातिय क्षेत्रा उपयोजना 1,33,72									
दत्तमत 17,01									
प्रभूत 37,48									
16,41,83									
9,69,40									
1,02,15									
1,33,72									
17,01									
37,48									
6,74,75									
16,41,83									
65,09									
12,68,74									
1,02,15									
2,36,32									
तालिका पृष्ठ 16 पर जारी ।।।।									

15

तालिका - 2 पृष्ठ 15 से जारी ।।।।

लेखे		आय-व्ययक अनुमान		संशोधित अनुमान		आय-व्ययक अनुमान		सहस्र रूपयों में	
2004-2005		2005-2006		2005-2006		2006-2007		2006-2007	
आयोजना भिन्न	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना भिन्न	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना भिन्न	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना भिन्न	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें	आयोजना भिन्न	केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनायें
24,82,37	58,94	26,78,92	7,54,07	27,25,87	1,30,70	28,47,10	3,36,85	65,09	32,49,04
3,32	"	1	"	1	"	1	"	"	1
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
40,76,90	2,18,46	44,34,24	8,15,83	46,05	1,92,75	46,89,37	3,77,53	1,13,57	51,80,47
3,64	"	3	"	3	"	3	"	"	3
40,80,54	2,18,46	44,34,27	8,15,83	46,05	1,92,75	46,89,40	3,77,53	1,13,57	51,80,50
UKSV% *दत्तमत व्यय (Voted Expenditure) : अधिकतर ऐसे व्यय होते हैं जो विधान सभा के मतदान द्वारा ही स्वीकृत किये जाते हैं तथा मतदान के समय कम किये जा सकते हैं लेकिन इन्में बड़ेतरी नहीं की जा सकती।									
प्रभूत व्यय (Charged Expenditure) : ऐसे व्यय होते हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद 202(6) के अन्तर्गत संशित निधि पर अनिवार्य रूप से प्रमांरित हैं। इन प्रमारो पर मतदान नहीं होता तथा इस व्यय को कम नहीं किया जा सकता। जैसे राज्पाब, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग आदि से संबंधित व्यय।									
Lkzksr% cV iqtLrk 2006&07]ktLFku ljckj									

16